हिन्दी साप्ताहिक

Title Code:- UTTBIL00534

उत्तराखण्ड अभ्युदय

♦वर्ष -01 ♦ अंक-14 ♦देहरादून - रविवार 26 जनवरी 2025 ♦पृष्ठ : 4 ♦मूल्यः 1/-

सीएम धामी का बड़ा एलान-इसी माह लागू होगा UCC

26 जनवरी को लागू कर सकती है सरकार, कैबिनेट ने 20 जनवरी को दी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली को मंजूरी

(संवाददाता)

देहरादून। उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) लागू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत में बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) इसी महीने यानी जनवरी में ही लागू किया जाएगा।

सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड कैबिनेट ने 20 जनवरी को इसकी मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने यूसीसी के लिए हमें जनादेश दिया है। हम वादा पूरा कर रहे हैं। किसी भी धर्म के लोगों टारगेट नहीं कर रहे है। यूसीसी लागू होने से तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों को परेशानी हो रही है। सीएम धामी ने संकेत दिया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इसी महीने के अंत में लागू किया जाएगा। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि किस तारीख हो यूसीसी लागू किया जाएगा लेकिन इतना संकेत जरुर दिया कि सरकार गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर यूसीसी लागू करने की घोषणा कर सकती है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार यूसीसी इसी महीने लागू करने की तैयारी कर रही है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। यूसीसी की गंगा देवभूमि से निकल रही है।

लिव इन रिलेशन में रहने वालों को हम मना नहीं कर रहेः धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे रहे हैं। सबके लिए समान व्यवस्था लागू कर रहे हैं। हलाला, बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। यूसीसी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। हम लिव इन रिलेशन में रहने से किसी को मना नहीं कर रहे। माता–पिता को अपने बच्चों की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए लिव इन में रहने वालों को अपने माता–पिता से इजाजत लेनी होगी। हमने श्रद्धा–आफताब जैसे केसों की स्टडी की है। प्राइवेसी खत्म करना नहीं, सुरक्षा हमारा उद्देश्य है।

कार्मिकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

अब कानून को धरातल पर उतारने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए ब्लाक स्तर तक राजस्व, पुलिस, स्थानीय निकाय, कैंट बोर्ड व अभियोजन आदि संबंधित विभागों के कार्मिकों की सूची तैयार हो रही है। सीएससी एसपीवी सभी अधिकारियों को समान नागरिक संहिता की प्रक्रियाओं को समझने और इन्हें लागू करने का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। अधिकारियों और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए तीन विभाग सहायता केंद्र स्थापित करेंगे। इनफारमेशन टेक्नालाजी डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए) तकनीकी सहयोग के लिए, सीएसएसी एसपीवी प्रशिक्षण के लिए और अभियोजन विभाग सभी हितधारकों को कानूनी सहायता प्रदान करने को इन केंद्रों का संचालन करेंगे।

समान नागरिक संहिता के मुख्य प्रावधान

- विवाह का पंजीकरण अनिवार्य
- पति–पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूरी तरह प्रतिबंधित
- सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार।
- सभी धर्म–समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटी–बेटी को संपत्ति में समान अधिकार।
- मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक।
- संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं।
- लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य।

पहचान छिपाकर रहने वालों पर होगा एक्शन

देहरादून। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप बने रहना चाहिए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में धार्मिक स्थल, मजार बना दिया। अतिक्रमण से साढ़े 5 हजार एकड़ जमीन मुक्त कराया गया है। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के हमने आदेश दिए। बांग्लादेशियों, रोहिंग्या लिंक की जांच के आदेश भी दिए हैं। पहचान छिपाकर रह रहे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा।

वेब पोर्टल व मोबाइल एप तैयार

देहरादून। प्रदेश में सरल व पारदर्शी तरीके से समान नागरिक संहिता लागू हो, इसके लिए वेब पोर्टल व मोबाइल एप तैयार कर लिए गए हैं। अब इनका परीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी माह राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। उत्तराखंड में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून बना चुकी है। इसे राष्ट्रपति भवन से स्वीकृति मिल चुकी है। इस कानून के प्रविधानों को लागू करने के लिए नियमावली बनाई जा चुकी है।

एसपीजी की एडवांस टीम पहुंची दून

सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

(संवाददाता)

देहरादून। उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियों जोर–शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के देहरादून दौरे को देखते हुए सुरक्षा–व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार 24 जनवरी को एसपीजी (विशेष सुरक्षा समूह) की एडवांस टीम कार्यक्रम स्थल रजत जयंती खेल परिसर देहरादून पहुंची।

इस दौरान जिला प्रशासन के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचेंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए

प्रधानमंत्री कार्यालय में करीब 2 घंटे तक अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक संपन्न होने के बाद करीब 6:00 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में बने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पहुंचेंगे। जहां पर राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया जाने को लेकर ओपनिंग सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लिहाजा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे।

सीसीटीवी की निगरानी में होगी मतगणना

तैयारियां पूरी, स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं सभी उम्मीदवार

(संवाददाता)

देहरादून। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। अब 25 जनवरी को मतगणना होनी है। ऐसे में मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा। मतगणना से पहले कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। हरिद्वार नगर निगम के आरओ लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि हरिद्वार नगर निगम के 60 वार्डों के मतों की मतगणना के लिए 25 टेबल लगाई गई हैं, जिनमें सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएग। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटियों को सुबह 7 बजे निकाला जाएगा।

लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा में रखा गया है और जो उम्मीदवार हैं, उनके अभिकर्ता भी स्ट्रांग रूम की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मतगणना शाम 8 बजे तक पूरी नहीं होती है, तो 8 बजे के बाद दूसरी शिफ्ट के कर्मचारियों को मतगणना के लिए लगाया जाएगा।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने कल होने वाली मतगणना को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ योजना बनाई और मतगणना स्थल पर कौन सा पार्टी का पदाधिकारी रहेगा, यह तय किया। मदन कौशिक ने कहा कि जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार की जनता ने कल मतदान किया है, उससे साबित हो रहा है कि इस बार मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। ऊधम सिंह नगर की 17 नगर निकायों की कल मतगणना होनी है। ऐसे में आज जिला प्रशासन द्वारा मतगणना में लगाए कर्मचारियों को दूसरी बार की ट्रेनिंग दी जा रही है। जनपद के नगरपालिका और नगर पंचायत की होने वाली मतगणना में लगभग एक हजार कर्मचारी लगेंगे, जबकि दो नगर निगमों में 500 कर्मचारियों को मतगणना में लगाया जाएगा।

प्रत्येक वार्ड के लिए एक टेबल

जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार जोशी ने बताया कि जनपद के नगर निकायों में 230 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए एक टेबल लगाई जाएगी, जिसमें एक वार्ड की एक टेबल पर चार कर्मचारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम रुद्रपुर और काशीपुर के लिए देर तक होने वाली काउंटिंग के लिए एक्स्ट्रा कार्मिकों को लगाया गया है।

सम्पादकीय

उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन

क्रीडया वर्धते वीर्यं संकल्प: साहसं धृति:।
अनुशासनं च सौहार्दं राष्ट्रस्य च महौजसम्
क्रीडाया:अभ्यासयोगेन बलं बुद्धिश्च वर्धते।।

अर्थात्
खेल के माध्यम से वीरता, संकल्प, साहस और धैर्य बढ़ता है। यह अनुशासन और मित्रता को प्रोत्साहित करता है और राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाता है। खेलों के अभ्यास से बल और बुद्धि दोनों का विकास होता है।

बेहद सुखद है कि देवभूमि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है।राष्ट्रीय खेलों का आयोजन केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, परिश्रम और आत्मसंयम का पाठ पढ़ाता है। खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों में धैर्य, साहस और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। प्रतिस्पर्धा के दौरान व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर नई ऊंचाइयों को छूता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि राष्ट्र को भी सशक्त और गौरवशाली बनाता है। खेलों में भाग लेने से व्यक्ति के भीतर संगठित जीवनशैली और समय प्रबंधन की भावना उत्पन्न होती है, जिससे वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।

खेलों से टीम वर्क, खेल भावना और अनुशासन का विकास होता है। खिलाड़ी मैदान में अपने प्रदर्शन से न केवल स्वयं को, बल्कि अपने देश और समाज को भी गौरवान्वित करते हैं। खेल स्वास्थ्य और मानसिक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। इसके अलावा, खेलों के माध्यम से राष्ट्र की एकता और सौहार्द की भावना भी बढ़ती है।

उत्तराखंड सरकार खिलाड़ियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं और उत्कृष्ट आतिथ्य प्रदान करने के लिए संकल्पित है।

उम्मीद है कि उत्तराखंड में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेल यहां की आर्थिकी और पर्यटन को भी नई ऊंचाई प्रदान करेगा और राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखरने का स्वर्णिम अवसर सिद्ध होगा।

जय देवभूमि उत्तराखण्ड!! जय भारत !!

डॉ. गार्गी मिश्रा

वन्यजीवों द्वारा मानवजीवन को खतरा

मानवी राजपूत

मानव और वन्य जीव संघर्ष एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। हालांकि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग की भारी-भरकम मशीनरी लाखों रुपए खर्च करती है लेकिन वह भी इस गम्भीर समस्या के आगे असहाय नजर आ रही है। आए दिन शहरों में खतरनाक वन्य जीव घुस आते हैं और मनुष्यों पर हमले कर देते हैं जिससे मौतें भी होती हैं और वन्य जीवों को भी पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार वन्य जीवों को भी जान से हाथ धोना पड़ता है। देश की राजधानी दिल्ली की एक रिहायशी बस्ती में आमदखोर तेंदुए ने घुसकर एक दर्जन लोगों पर हमला किया। उसके हमले में पांच लोग घायल हो गए। पूरे इलाके में खौफ कायम है। इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। इससे पहले भी पिछले वर्ष दिसम्बर में हाई प्रोफाइल इलाके सैनिक फार्म में तेंदुए ने दहशत फैला दी थी। हालांकि कई घंटों बाद उसे दबोच लिया गया था। महानगरों में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और कुछ अन्य राज्यों में ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। अब सवाल यह है कि वन्य जीवों के शहरों में घुसने की समस्या के लिए जिम्मेदार किसे माना जाए। क्या इसके लिए केवल वन विभाग को जिम्मेदार माना जाए या फिर मानव को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए। कोई जानवर किसी इंसान की जान का दुश्मन कब बनता है? आज क्यों दोनों ही एक-दूसरे की बलि लेने पर अमादा हो जाते हैं? आखिर वन्य प्राणी अपने आश्रय स्थलों को छोड़ने के लिए विवश क्यों हुए? दरअसल वनों पर अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप ही वन्य जीवों के साथ मानव के संघर्ष का प्रथम कारण बना। वनों का व्यावसायिक उपयोग, उद्योग जगत का विस्तार और आधुनिक जीवनशैली तथा बाजारीकरण और नगरीय सभ्यता के विकास ने दुनिया के कोने-कोने में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। सड़कों का जाल ऐसे बिछा कि जंगल के बाशिंदे भोजन और आवास के लिए तरसने लगे। परिणामस्वरूप उनका पदार्पण मानव बस्तियों की ओर होने लगा। तो क्या विकासपरक नीतियां ही मानव और वन्य जीवों के संघर्ष के पीछे महत्वपूर्ण कारक है? जंगलों के दोहन के साथ सेंचुरी और नेशनल पार्क के निर्माण ने वनों के आस-पास निवास करने वाले स्थानीय निवासियों को उनके हक से वंचित किया है। जबकि यह वही स्थानीय निवासी थे जिन्होंने सदियों से बिना व्यावसायिक दोहन के हमेशा वनों का उचित उपयोग करते हुए उसके संरक्षण का भी काम किया था। विडंबना ही कहेंगे कि इस मुद्दे को सिरे से नकार दिया जाता है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विमर्श हाशिये के समाजों की जीवनशैली को समझने में असमर्थ ही रहे हैं।

सरकार जंगलों को बचाने के लिए भले ही लाख प्रयास करे लेकिन हकीकत यह है कि वन्य क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं। जंगल काट-काट कर रिहायशी कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं। पर्यटन के नाम पर जंगलों को कमाई का केन्द्र बना दिया है। वन क्षेत्र में सफारी और जंगल रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। इस सबसे वन्य जीवों की निजता का हनन हो रहा है। यही कारण है कि वन्य जीव इंसानी बस्तियों में आने लगे हैं। इतने सारे वन्य संरक्षण पार्क और सेंचूरी बन जाने के बावजूद वन्य जीवनों का हमला बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस समस्या के कई अन्य कारण भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों में शिकार की कमी और पानी की कमी भी वन्य जीवों का शहरों की तरफ आना भी कारण है। यह एक ऐसी समस्या है जो पहाड़ी राज्यों के जीवन, जीविका और समाज को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उत्तराखंड के गांव में रहने वाले लोग आमदखोर जानवरों के आतंक की वजह से अपने गांव छोड़कर शहरी इलाकों में बसने लगे हैं।

संविधान के मूल ढांचे से किसी भी तरह के खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

अनुभा गौर

विपक्ष बहुत शोर मचा रहा है कि हमारा लोकतंत्र खष्तरे में है और अगर नरेंद्र मोदी की भाजपा फिर सत्ता में आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा। भाजपा के अपने कुछ गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा यह प्रचार कि अगर 400 से अधिक सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे से इस शंका को बल मिला है। पर ऐसे नहीं होने वाला। पहली बात तो यह है कि जनता संविधान के मूल ढांचे से किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंदिरा गांधी को सबक सिखाया जा चुका है। लोगों को अपने लोकतंत्र, वह कैसा भी अपूर्ण हो, से मोह है। दूसरा, न ही भाजपा का नेतृत्व संविधान बदलने की बात कर रहा है। तीसरा, भाजपा के नेतृत्व को संविधान बदलने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसी संविधान के अंतर्गत उनका काम बढ़िया चल रहा है और उनके मुद्दे, धारा 370 हटाना, राममंदिर निर्माण आदि पूरे हो रहे हैं। चौथा, संविधान बदलने के लिए जो बहुमत चाहिए वह भी किसी को मिलने वाला नहीं। 400 पार केवल प्रचार के लिए है। प्रदेशों के बहुमत का अनुमोदन भी चाहिए। केवल एक बार राजीव गांधी को ऐसा बहुमत मिला था पर उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया था।

जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद यह चुनाव एक व्यक्ति, नरेन्द्र मोदी पर केन्द्रित है। भाजपा भी उन्हीं का नाम जप रही है और विपक्षी निशाने पर भी नरेन्द्र मोदी ही है। वरिष्ठ नेता जैसे राजनाथ सिंह या अमित शाह या नितिन गड़करी भी केवल एक ही नाम पर वोट मांग रहे हैं, नरेन्द्र मोदी। सब कुछ 'मोदी की गारंटी' है। प्रचार में भी एक ही चेहरा नजर आता है। संघ जो व्यक्ति- विशेष के प्रचार को पसंद नहीं करता ने भी समझौता कर लिया है। मोदी भी इस चुनाव कोप्रेसिडेंशियल टाईप बनाने में सफल रहे हैं क्योंकि उनके सामने राहुल गांधी फीके लगते हैं। वह 2047 तक विकसित भारत का वादा कर रहें हैं और जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की गारंटी दे रहे हैं। संदेश स्पष्ट है कि यह सब केवल एक नेता की लीडरशिप में ही हो सकता है। विपक्ष का भी सारा हमला नरेन्द्र मोदी पर हो रहा है। समझ गए हैं कि उनके बिना भाजपा बिन पतवार के नौका की तरह होगी,इसलिए प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर चोट की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के बावजूद उनका 370/400 वाला दावा जरूरत से अधिक आशावान नजर आता है। इतनी बड़ी छलांग के लिए पक्ष में बड़ी लहर चाहिए जो अभी नजर नहीं आ रही। उल्टा वोटर थका थका सा नजर आ रहा है और कार्यकर्ता उदासीन है। भाजपा ने भ्रष्ट और दलबदलुओं को दाखिल कर अपना नुकष्सान कर लिया है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उसी दिन खोखला हो गया था जब अजीत पवार जैसों को साथ लिया था। परिवारवाद का मुद्दा भी इसी कारण खो दिया। भाजपा के अंदर इस बात को लेकर असंतोष है कि दूसरे दलों से आए लोगों को तरजीह दी जा रही है। पंजाब में तो सारा संगठन ही कांग्रेस से आए लोगों को सौंप दिया गया है। बिहार में नीतीश कुमार का साथ महंगा प्रतीत होता है। महाराष्ट्र (48) और बिहार (40) दोनों में पिछली वाली बात नहीं है। उत्तर में किसान नाराज है जिसका असर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। 2019 के चुनाव में बालाकोट और पुलवामा के भावनात्मक मुद्दे थे। आज ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। 2047 किस ने देखा है? 'इंडिया शायनिंग' वाला प्रयास दोहराया जा रहा लगता है। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता के मुद्दे परेशान कर रहे हैं। उत्तर भारत में अग्निवीर भर्ती योजना भी बड़ा मुद्दा है। चार साल के बाद जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे वह नौजवान किधर जाएंगे? काश, इसे लागू करते समय इसके दूरगामी परिणामों का सही आंकलन किया होता। अगर 370/400 प्राप्त करना है तो दक्षिण भारत में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। 2019 में दक्षिण की 130 सीटों में से भाजपा को केवल 29 सीटें मिली थीं जिनमें से 25 कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से थी। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वह खाता नहीं खोल सके थे। आज कर्नाटक और तेलंगाना दोनों में मजबूत नेताओं के नीचे कांग्रेस की सरकारें हैइसलिए पिछले वाला समर्थन नहीं मिलेगा। यह अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री ने फिर मुसलमानों का मुद्दा उठा लिया है। इस चुनाव में 'मंगलसूत्र','घुसपैठिए','जिनके ज्यादा बच्चे हैं ' कहां से टपक गए? इसकी जरूरत भी क्या थी? इससे यह प्रभाव मिलता है कि अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है इसलिए फिर हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से लिखा है कि वहां यह आवाजें सुनने को मिल रही हैं कि, "बहुत हो गया हिन्दू -मुसलमान। रहना तो साथ में ही है"। न ही इस बार राम मंदिर ही मुद्दा है। बेहतर होता कि देश के प्रधानमंत्री खुद को निम्न राजनीति से ऊपर रखते। जब संदेश 'सबका साथ और सबका विकास' है और सब कल्याणकारी योजनाओं में सबका बराबर का हिस्सा है, तो ध्रुवीकरण करने की क्या जरूरत है? हाल में किए गए सीएसडीएस-लोकनीति सर्वेक्षण के अनुसार 27 प्रतिशत लोग बेरोजगारी को और 23 प्रतिशत लोग महंगाई को मुख्य मुद्दा मानते हैं। केवल 2 प्रतिशत ही हिन्दुत्व को मुद्दा मानते हैं। उम्मीदवार घोषित करने में कांग्रेस सबसे पीछे है। अभी तक यह ही नहीं बताया जा रहा कि रायबरेली और अमेठी से कौन लड़ेगा? राहुल गांधी का जवाब था कि हाईकमान फैसला करेगा। पर भैया, आप ही तो हाईकमान हो,खुद से पूछ लो ! कांग्रेस से जो होलसेल दलबदल हो रहा है वह नेतृत्व के प्रति अविश्वास बताता है। 2019 में भाजपा और कांग्रेस के वोट में लगभग 18 प्रतिशत का अंतर था। इस खाई को पाटने के लिए 9-10 प्रतिशत की बड़ी छलांग चाहिए जो सम्भव नहीं लगती। राहुल गांधी की शिकायत है कि भारत सरकार के 90 सचिवों में केवल 3 ओबीसी हैं। उनके अनुसार "किस प्रकार बजट का वितरण होता है उसमें भारत की जनसंख्या के 90 प्रतिशत की कोई भूमिका नहीं"। यह न केवल पिछड़ी सोच है बल्कि बहुत खष्तरनाक भी है कि केवल एक ओबीसी, एक दलित या आदिवासी या अल्पसंख्यक अफसर ही अपने समुदाय का हित देख सकता है। ऐसे तो देश के बिल्कुल टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। उनके अनुसारजाति जनगणना देश की हर समस्या का इलाज है। नेहरूजी की विचारधारा का उनके ही वंशज शीर्षासन कर रहे हैं। वह देश का एक्स-रे करने की धमकी दे रहे हैं और 'देश के धन' के पुनर्वितरण की बात कर रहें हैं। देश में जो घोर विषमता देखने को मिल रही है वह अत्यंत चिन्ता की बात है इसके लिए नीतियां बदलनी होंगी पर राहुल गांधी तो जबरदस्ती करने की बात कर रहें है, क्रान्तिकारी कदम उठाने की बात कर रहे हैं। क्या वह देश में सिविल वार चाहतें हैं?

राहुल तो अपने घोषणा पत्र से भी आगे निकल गए हैं। उनका नारा है 'जितनी आबादी उतना हकष'। यह होगा कैसे? क्या जज भी आबादी के अनुसार नियुक्त होंगे? सेना के जनरल भी? कांग्रेस पार्टी के शिखर पर गांधी परिवार का हकष भी कैसे बनेगा? राहुल अल्ट्रा- लैफ्ट की चरम विचारधारा से प्रभावित लगते हैं जिसे बीजिंग और मास्को तक रद्द कर चुके हैं। यह माओत्सी तुंग या लेनिन का युग नहीं है। न ही उनके गठबंधन की पार्टियां उनकी चरम विचारधारा को समर्थन देंगी। उन्हें खुद को महंगाई, बेरोजगारी और हैल्थ केयर जैसे मुद्दों तक सीमित रखना चाहिए। होश के बिना जोश के कारण उन्होंने एक बार फिर सेल्फ गोल कर लिया है।

सही तकिये का करें चुनाव

कुछ लोगों को तकिये के बगैर अच्छी नींद आती है तो कुछ लोग तकिये के बिना सो ही नहीं पाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि तकिये का गलत चुनाव कई सीरियस हेल्थ से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो आइए आज हम आपको बता रहे हैं कि गलत तकिया प्रयोग करने से क्या समस्याएं हो सकती हैं और सही चुनाव के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा।

एलर्जी

रुई के तकिये सबसे अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कई लोगों को इनके कारण एलर्जी, खासकर मुंह, नाक और आंखों में इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है। ऐसे में फाइबर का तकिया यूज कर सकते हैं।

नींद न आना

ज्यादा ऊंचा तकिया लगाने से सिर और कंधों के बीच का गैप ज्यादा हो जाता है। ऐसे में ठीक तरह से नींद नहीं आती।

गर्दन का दर्द

ज्यादा सॉफ्ट तकिये का प्रयोग करने से बॉडी पॉश्चर बिगड़ता है। ऐसे में गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक लाइन में नहीं रहते। इसके कारण गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है।

सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस

बहुत हार्ड तकिया लगाकर सोने पर बॉडी को पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता। सिर पर दबाव भी पड़ता है। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो सकती है।

पिंपल्स

तकिये का कवर ज्यादा दिन तक बिना धोए यूज किया जाए तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया के कारण पिंपल्स हो जाते हैं।

ब्लड सर्कुलेशन

ज्यादा ऊंचा तकिया यूज करने से ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पाता। ऐसे में स्किन और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

खर्राटे

तकिया बहुत मोटा हो तो गर्दन ठुड्डी की तरफ झुक जाती है। इससे खर्राटे आने की समस्या हो सकती है। ऐसे ही तकिया बहुत पतला होने पर सांस की नली थोड़ी बंद हो जाती है, जिससे खर्राटे आते हैं।

सही का ऐसे करें चुनाव

हार्ड या सॉफ्ट

तकिया न तो बहुत सॉफ्ट हो, न ही ज्यादा हार्ड। इसे सेमिरिजिड होना चाहिए, जिस पर सोएं, तो हल्का सा दबे।

चौड़ाई

तकिया आपके कम्फर्ट के हिसाब से चौड़ा होना चाहिए, पर यह भी देखें कि उससे कंधों को पूरा सपोर्ट मिल सके।

चेहरे की सफेद फुंसियों से यूं पाएं छुटकारा

चेहरे पर निकलने वाली सफेद फुंसियों को मिलिया भी कहते हैं। यह दिखने में सफेद या पीले रंग के होते हैं जो कि ज्यादातर आंखों के नीचे या फिर नाक, गाल, माथे और सीने पर उभरते हैं। मिलिया अक्सर छोटे बच्चों के चेहरे पर ज्यादा दिखते हैं। ये केराटिन से भरे सिस्ट होते हैं जो कि घातक नहीं होते। ये फुंसियां कुछ हफ्तों में गायब तो हो जाती हैं लेकिन इसकी वजह से दर्द दिक्कत होता है। यह कई कारणों से हो सकती है जैसे स्किन प्रॉडक्ट्स, सूरज की धूप या लंबे समय तक स्टिरॉयड क्रीम लगाने आदि की वजह से। अगर आपको लगता है कि आपको मिलिया की समस्या कई हफ्तों से परेशान कर रही है, तो आज हम कुछ उपाय बता रहे हैं, जिनसे इसे दूर किया जा सकता है।

अनार के छिलके का पाउडर

अनार के छिलके में ऐंटिऑक्सिडेंट होता है जो अच्छा होता है। अनार के छिलके को एक तवे पर भूरा होने तक रोस्ट कर लें और फिर उसे पीस कर पाउडर बना लें। फिर उसमें नींबू या गुलाब जल मिक्स करें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं, फायदा होगा।

चेहरे को गर्म तौलिए से सेंकें

गर्म पानी में तौलिए को भिगो कर निचोड़ कर चेहरे पर ढंके। ऐसा रोजाना कुछ हफ्तों तक करें। या फिर चेहरे को 10-15 मिनट के लिए स्टीम दें। ऐसा करने से चेहरे के बंद पोर्स खुल जाएंगे और डेड सेल निकल जाएगी।

शहद

चेहरे पर शुद्ध शहद लगा कर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। ऐसा रोज करें जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए। चाहें तो शहद में ओट्स और शक्कर मिला कर स्क्रब बना सकते हैं।

आपको हैरत में डाल देंगे पपीता खाने के ये 5 फायदे

स्वाद में मीठा, ताज़ा पपीता आपको सालभर बाजार में मिल जाएगा. पपीते में काले रंग के सैकड़ों संलग्न बीज होते है इसके केवल नरम भाग खाया को जाता है. आपके घर के सामने कुछ जमीन है तो आप इसका पेड़ भी लगा सकते हैं. ये एक ऐसा फल है जिसे कुछ स्थानों पर कच्चे पपीते का उपयोग सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. पपीता लेने के संभावित स्वास्थ्य लाभों में मुख्यत: पाचन में सहायता, मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार, रक्तचाप कम करने, और घाव भरने में सुधार, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर का खतरा कम करना इत्यादि शामिल है. आइए जाने की पपीते को अपनी दैनिक आहार योजना में जोड़ना क्यों जरूरी है:- कोलेस्ट्रॉल कम करन में सहायक : पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है. साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है. अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है. वजन घटाने में : एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है. ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें. इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं. रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में : रोग प्रतिरक्षा क्षमता अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहती हैं. पपीता आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी की मांग को पूरा करता है. ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मात्रा में पपीता खाते हैं तो आपके बीमार होने की आशंका कम हो जाएगी. पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में : जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द की शिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए. पपीते के सेवन से एक ओर जहां पीरियड साइकिल नियमित रहता है वहीं दर्द में भी आराम मिलता है. आंखों के लिए अच्छा : पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता ही है साथ ही विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है. विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है.

मुख्य सचिव रतूड़ी की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति में विभिन्न कार्यो की स्वीकृति

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय लोहाघाट

के भवन एवं छात्रावास के अवशेष निमार्ण कार्यों, नैनीताल में कैंची धाम में सौन्दर्यीकरण एवं प्रकाशकीय कार्यों में बहुमंजिली कार पार्किंग, पैदल सेतु निर्माण तथा श्रीबद्रीनाथ धाम में पावर ग्रेड द्वारा प्रायोजित वन वे लूप रोड और राज्य मुखौटा संवर्धन कार्य के निर्माण, लेकफ्रन्ट डेवलपमेंट शेषनेत्र लेक के निर्माण कार्य, श्रीबद्रीनाथ धाम में एनटीपीसी द्वारा प्रायोजित आईएसबीटी भवन नवीनीकरण और पार्किंग विकास (चरण ए) के पुनरीक्षित आगणन के निर्माण कार्य तथा महासू देवता हनोल में लंगर हॉल तथा धर्मशाला निर्माण के कार्यों को सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में अनुमोदन दिया। बैठक में सचिव नितेश कुमार झा सहित नियोजन, वित्त, पर्यटन, शिक्षा एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बंद हुआ चुनाव प्रचार का शोर , डोर टू डोर जनसंपर्क में लगे प्रत्याशी

देहरादून। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर मंगलवार को शाम पांच बजे थम गया। अब चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर मतदाताओं को साधने में जुटेंगे। इस बीच मंगलवार को प्रदेशभर में विभिन्न दलों ने अपने प्रत्याशियों के हक में कई छोटी-बड़ी जन सभाएं कीं। बाइक रैली के साथ नुक्कड़ सभाएं भी कीं। कुछ स्थानों में स्थानीय कलाकारों को मंच पर बुलाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए जोर लगाया गया। इस संबंध में सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग राहुल कुमार गोयल की ओर से मतदान के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार-प्रसार एवं सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित करने के निर्देश सभी जिलों को दिए थे। अब 23 जनवरी को 11 नगर निगमों में मेयर के 72 प्रत्याशी, नगर पालिका व नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। प्रदेशभर में 30 लाख 29 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव के लिए कार्मिकों का मंगलवार को द्वितीय चरण का प्रशिक्षण भी पूरा हो गया।

नशा मुक्ति केंद्र से भागे युवक ने की बंद घर में चोरी

देहरादून। नशा मुक्ति केंद्र से भागे युवक ने फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक के बंद घर में चोरी की। बीते शनिवार को पटेलनगर थाना क्षेत्र में हुई घटना का मंगलवार को पटेलनगर थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक सुनील कुमार का मकान गणेशपुर में बिजली घर के पास है। बीते शनिवार सुबह साढ़े नौ बजे वह घर का ताला लगाकर ड्यूटी चले गए। ड्यूटी से ससुराल पहुंचे। ससुराल से जुड़े रिश्तेदार पटेलनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती थे। सुनील पत्नी संग उनका हालचाल लेने अस्पताल चले गए। रात करीब दस बजे घर वापस पहुंचे। इस दौरान मुख्य दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो नजारा देखकर होश उड़ गए। अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। लॉकर और अटैचियां टूटी थी। चोर घर में खड़ा स्कूटर, सोने की अंगूठी, चेन, कुंडल, चांदी की तीन जोड़ी पायल और दस हजार रुपये नगदी चुराकर ले गए। सुनील ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। रविवार को उन्होंने नया गांव चौकी पहुंचकर तहरीर दी। जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर पटेलनगर केके लुंठी ने चोरी के मामले में चेकिंग के दौरान शिमला बाईपास रोड से विकास थापा उम्र 22 वर्ष निवासी चीला हाईडिल कॉलोनी, लक्ष्मणझूला, जिला पौड़ी को गिरफ्तार किया गया। उससे चोरी किया गया दुपहिया और करीब एक लाख रुपये के गहने बरामद किए गए।

प्रभारी मंत्री सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने निकाय चुनाव में झौंकी ताकत

हरिद्वार। निकाय चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद भट्ट और जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने नगर पालिका शिवालिक नगर से अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा और भाजपा पार्षद पद के समस्त प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल चुनावी रैली के माध्यम से जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद भट्ट और वरिष्ठ भाजपा नेता एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने मंगलवार को नगर पालिका शिवालिक नगर से अध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी राजीव शर्मा सहित भाजपा पार्षद पद के समस्त प्रत्याशियों के समर्थन में

विशाल चुनावी रैली के माध्यम से जनता से भाजपा को जितने की अपील की। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में लगातार विकास की गंगा बह रही है।

महाराज ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विकास के लिए जरूरी है कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का पररचम लहराये और ट्रिपल इंजन की सरकार बने। इस मौके पर भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने रैली के दौरान अपने अपने वाहनों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया।

कांग्रेसकाल में निकायों के विकास को हुए थे महत्वपूर्ण निर्णयः माहरा

देहरादून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने लोगों से कांग्रेस के हक में मतदान की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जिस तरह से पूर्व निकायों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही विकास की सोच रखती है। मीडिया को जारी बयान में माहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने बिजनेस प्रोसेस रीइंजिनियरिंग योजना की स्वीकृत करने के साथ ही राज्य के नगरीय क्षेत्र के आवासों के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए मल्टी परपज हाउस होल्ड सर्वे योजना शुरू थी। जिससे पेयजल, विद्युत व्यवस्था, शिक्षा और यातायात की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके। नगरीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कहा कि स्व. राजीव गांधी ने प्रत्येक शहर की अपनी सरकार का जो सपना देखा था, वह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में संविधान के 74वें संविधान संशोधन के रूप में कांग्रेस ने पूरा किया।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के विकास के लिए पर्यटन उद्योग को ऐसा उद्योग मानती है, जिससे सुदूर पर्वतीय अंचलों का विकास हो सकता है और रोजगार के असीमित अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे शहरों की अवस्थापना सुविधाएं अति उच्च स्तर की हों।

इधर, पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि शहरों में निवास कर रहे कमजोर वर्ग हमेशा कांग्रेस की प्राथमिकता रहे हैं। इनके कल्याण के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), मलिन बस्ती सुधार योजना (एनएसडीपी), बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वीएएमबीएवाई) का व्यापक क्रियान्वयन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार ने 10 अगस्त, 2016 को मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने के संबंध में अधिनियम लागू किया था। उन्होंने लोगों से कांग्रेस के हक में वोट की अपील की।

वीर गिरवाली में जमीन बेचने की डील कर हड़प लिए १.२० करोड़

देहरादून। जमीन बेचने की डील कर एक व्यक्ति से 1.20 करोड़ रुपये हड़प लिए गए। मामले में राजपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। जमीन वीर गिरवाली इलाके में दिखाई गई। अश्वनी कोहली निवासी जनक पार्क, हरि नगर, नई दिल्ली की तहरीर पर राजपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया कि उनकी और अमरीश गोयल निवासी ओल्ड राजपुर की अच्छी जान-पहचान थी। अमरीश ने पहले एक जमीन पीड़ित को बेची थी। इसके बाद पीड़ित का उन पर विश्वास और बढ़ गया। इस भरोसे का फायदा उठाकर अमरीश गोयल ने ओल्ड मसूरी रोड स्थित वीरगिरवाली और राजपुर माफी में जमीन बेचने का प्रस्ताव दिया। 10 जनवरी 2024 को दोनों पक्षों के बीच सब-रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में दो पंजीकृत अनुबंध पत्र तैयार किए गए। अमरीश ने पीड़ित से 1.20 करोड़ रुपये एडवांस भुगतान के तौर पर ले लिए। एक महीने के भीतर रजिस्ट्री का वादा किया। निर्धारित तारीख 11 फरवरी 2024 को जब अश्वनी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचे, तो अमरीश वहां नहीं आए।

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आर्फसेट प्रिंटर्श 64 नेशविला रोड़ देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेन्ट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादकः
गार्गी मिश्रा
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।